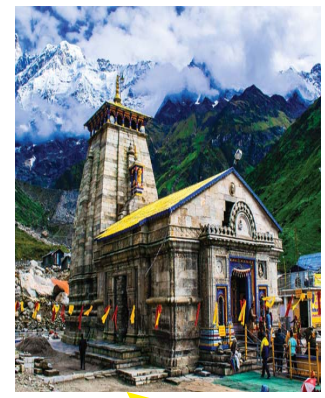

हिन्दी दैनिक
पथ प्रवाह
RNI No.: UTTHIN/2011/39282
हर खबर पर पैनी नजर

वर्षः5 अंकः04 पृष्ठः08 मुल्यः1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, बुधवार, 07 जनवरी 2026

वीबी-जी राम जी अधिनियम से गांव होंगे सशक्त और आत्मनिर्भरः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (ड्ढक्क-त क्रूत) अधिनियम को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह केवल मनरेगा का नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की संरचनात्मक पुनर्रचना है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम गांवों को मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम के माध्यम से किसानों को सुरक्षा, श्रमिकों को स्थायी रोजगार, महिलाओं को सम्मान और गांवों को विकास की नई गति मिलेगी। विकसित गांवों के माध्यम से विकसित भारत की मजबूत नींव रखने में यह कानून अहम भूमिका निभाएगा।

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार पाने का कानूनी अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25 प्रतिशत अधिक है। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की तय की गई है। साथ ही, भुगतान की प्रक्रिया को साप्ताहिक किया गया है और विलंब होने पर मुआवजे का प्रावधान भी रखा गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वीबी-जी राम जी को भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी योजना बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग, तद्धस् मैपिंग, मोबाइल ऐप, सार्वजनिक डैशबोर्ड,ऽद्ध आधारित फ्रॉड डिटेक्शन तथा वर्ष में दो बार अनिवार्य सोशल ऑडिट शामिल हैं।

उन्होंने किसानों के हितों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बुवाई और कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के कार्य कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, जिससे खेती के समय मजदूरों की कमी न हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम में ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को वास्तविक अधिकार दिए गए हैं। विकास कार्य ऊपर से थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा द्वारा ही चिन्हित किए जाएंगे। कम से कम 50 प्रतिशत कार्य सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाएंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण और योजना निर्माण जैसे निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाएंगे।

वीबी-जी राम जी के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका परिसंपत्तियां और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इनमें तालाब, चेकडैम, स्टॉपडैम, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, एसएचजी शेड, स्किल सेंटर, ग्रामीण हाट, रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज और पिचिंग जैसे कार्य शामिल होंगे। इससे रोजगार भी मिलेगा और गांवों की बुनियादी संरचना भी मजबूत होगी।

महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए स्किल सेंटर, शेड निर्माण और ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे, जिससे उन्हें गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट और तकनीकी सहायकों के प्रशिक्षण, मानदेय और निगरानी के लिए प्रशासनिक खर्च 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है। वित्तीय प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का वित्तीय अनुपात तय किया गया है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य को केंद्र सरकार से 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पर्वतीय और आपदा-संवेदनशील राज्य होने के कारण उत्तराखंड में यह अधिनियम जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने में विशेष भूमिका निभाएगा। उन्होंने एसबीआई के विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि इस अधिनियम से राज्यों को लगभग 17,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वीबी-जी राम जी योजना गरीब विरोधी नहीं, बल्कि गरीबी के मूल कारणों पर सीधा प्रहार है। इसमें श्रमिकों को अधिक काम, समय पर वेतन, कानूनी जवाबदेही और तकनीक आधारित पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और विधायक दिलीप रावत भी उपस्थित रहे।

श्रम कानूनों पर अमल के लिए राष्ट्रपति ने उप राज्यपालों तथा प्रशासकों को दिये अधिकार

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में नये श्रम कानूनों को पारदर्शिता के साथ लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए उप राज्यपालों तथा प्रशासकों को सरकारों के अनुरूप अधिकारों का निर्वहन करने की अनुमति दे दी है। ये अधिकार औद्योगिक संबंध संहिता 2020 तथा संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंध (1) के अनुरूप हैं और 16 जनवरी 2023 तथा 22 जून 2023 की जगह लेंगे।

गृह मंत्रालय ने दो जनवरी को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नयी अधिसूचना से पहले जारी अधिसूचना के तहत लिए गये निर्णय प्रभावित नहीं होंगे।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर के प्रशासक या उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अंतर्गत उन क्षेत्रों के लिए, जहां संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के रूप में कार्य करना अपेक्षित है, उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

जानकारों का कहना है कि उप राज्यपालों और प्रशासकों को ये अधिकार इसलिए दिये गये हैं जिससे कि श्रम सुधारों को पूरी तरह लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आये। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार श्रम कानूनों के प्रभावी अमल के लिए स्पष्ट प्रशासनिक अधिकार होना जरूरी हैं जिससे कि किसी संदेह या विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी जल्द निर्णय ले सकें।

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची जारी, दो करोड़ 89 लाख नाम हटे; दावे-आपत्तियों के बाद अंतिम सूची छह मार्च को

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत मंगवार को जारी नयी सूची के मसौदे में पिछली सूची के लगभग दो करोड़ 89 लाख (18.70 प्रतिशत) नाम हट गये हैं।

मसौदा सूची को लेकर छह फरवरी तक दाये और आपत्तियां दाखिल करायी जा सकेगी। इसके साथ ही अब अधिकारी उन मतदाताओं को नोटिस भी जारी कर सकते हैं जिनके बारे में जांच और कुछ प्रमाण की आवश्कता है। राज्य नयी सूची छह मार्च को प्रकाशित की जाएगी।

राज्य में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के लिए आधार बनायी गयी पिछली मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी जो आज जारी नयी सूची के मसौदे में 12.56 करोड़ रह गई है। मृत्यु, अनुपस्थिति, राज्य से स्थायी रूप से बाहर जाने या एक से अधिक जगह पंजीकृत पाये जाने के कारण लगभग 18.70 प्रतिशत नाम सूची से बाहर हो गये हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को सूची का मसौदा जारी की। गत 27 अक्टूबर को पूरानी सूची में प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता पंजीकृत थे। एसआईआर के लिए मतदाता गणना फार्म जमा करने की अवधि बढ़ाये जाने के बाद भी पिछली सूची में दर्ज मतदाताओं में से 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 के गणना-प्रपत्र प्राप्त हुए, जो पिछली सूची के कुल मतदाताओं का 81.30 प्रतिशत है।

श्री रिणवा ने कहा , 'एसआईआर में चार नवंबर 2025 से शुरू किये गये गणना चरण शुरू होकर 26 दिसंबर 2025 तक 12 करोड़ 55 लाख (81.30 प्रतिशत) मतदाताओं के गणना-प्रपत्र प्राप्त हुए।' उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारियों के घर-घर जा कर पुनरीक्षण किये जाने की प्रक्रिया में 46,23,796 (2.99 प्रतिशत) मतदाता मृत पाए गए और 79,52,190 मतदाताओं का कोई पता नहीं चला। इसके अलावा 1,29,77,472 मतदाता अन्यत्र जा चुके हैं तथा 25.47 लाख मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए, जिनके नाम सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। ऐसे मामलों में मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा और चुनाव आयोग के मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 15,430 नए मतदान स्थल तय किये गए हैं। इससे एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। रिणव ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में सभी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सक्रिय सहयोग रहा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इन दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं और उन्हें नयी मतदाता सूची के मसौदे की सॉफ्ट कॉपी एवं छपी प्रतियां उपलब्ध करा दी गयी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ इस प्रक्रिया में अब तक 1546 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

मसौदा सूची के जारी होने के साथ छह जनवरी से छह फरवरी-2026 तक मसौदा सूची पर दावे एवं आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। यदि किसी वैध मतदाता का नाम आज जारी नयी सूची के मसौदे में नहीं है तो वह फॉर्म-6, 6क, 7 एवं 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, उसमें संशोधन कराने का दावा या किसी नाम को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिन मतदाताओं की पहचान नहीं लग सकी है उन्हें बीएलओ के माध्यम से इस दौरान नोटिस भेजे जाएंगे। ऐसे मतदाता इस अवधि में अपने माता-पिता के नाम सहित अपना विवरण सही करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस दौरान अब तक नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 15 लाख 78 हजार 423 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि आयु पात्रता के अनुसार 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम इस सूची में शामिल होंगे, जबकि एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वालों के नाम बाद में अक्टूबर माह में जोड़े जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद छह मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। घोषणा की कि प्रति बूथ 1500 से 1200 वोटर्स के हिसाब से पोलिंग बूथ को तर्कसंगत बनाने के बाद, अब राज्य में 15430 नए बूथ जोड़े गए हैं।

परिवहन विभाग की सराहनीय पहल, एनसीसी कैडेट्स को दिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण

पथ प्रवाह, हरिद्वार। परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पतंजलि यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के तत्वावधान में National Cadet Corps (NCC) एवं National Disaster Response Force (NDRF) के संयुक्त सहयोग से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम एवं फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सहायक संभागीय अधिकारी नेहा झा ने बताया कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों, दुर्घटना के तुरंत बाद अपनाए जाने वाले सुरक्षित व्यवहार, गोल्डन आवर की महत्ता, घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार, सीपीआर (CPR), रक्तस्राव रोकने, स्ट्रेचर आदि का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। NDRF के प्रशिक्षकों द्वारा आपदा एवं सड़क दुर्घटना की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रिया

(First Response) के मानक प्रोटोकॉल का डेमो भी प्रस्तुत किया गया। NCC कैडेट्स एवं विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लिया और सड़क सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षित प्रथम रिस्पॉन्डर बनने से दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं गंभीर चोटों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों से यातायात नियमों के पालन, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, ओवरस्पीडिंग एवं नशे में वाहन न चलाने की शपथ दिलाई गई। यह आयोजन सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा तथा युवाओं को जिम्मेदार नागरिक एवं प्रशिक्षित प्रथम सहायक के रूप में तैयार करने में सहायक बनेगा।

एक नजर

प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देश पर नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जनपद पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही के सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में रुड़की पुलिस ने एक नशा तस्कर को प्रतिबंधित कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली रुड़की पुलिस ने के मुताबिक एक नशा तस्कर को अवैध नशीले कैप्सूल्स के साथ नगला ईमरती क्षेत्र से दबोचा। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरु कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम नदीम पुत्र इस्माइल निवासी नगला ईमरती थाना कोतवाली रुड़की है। उसके पास से प्रति?बंधित 174 नशीले कैप्सूल और अन्य दवाई बरामद हुई है। नशीली दवा बेचकर कमाए 2 हजार रुपये भी उसके पास से पुलिस को मिले हैं।

नशा तस्करों पर हरिद्वार पुलिस का प्रहार, फरार चल रहे तीन गैंगस्टर गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार में नशा तस्करों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा चलाये जा रहे अभियान को सफल बनाने के क्रम में जनपद पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना सिडकुल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरोह बनाकर नशे की तस्करी करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई तथा थाना सिडकुल पर मुकदमा अपराध संख्या 1/26 धारा 2(ड्र)(द्वद्व)(×द्व)/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम सागर आदि पंजीकृत किया गया था। जिसपर कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे हैं अभियुक्त अंशुल पुत्र जसवीर निवासी बझेडी सरकारी स्कूल के पास थाना ऊन जिला शामली उत्तर प्रदेश, आदित्य पुत्र श्रवण निवासी देवनगर रावली महदूद थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार और राहुल पुत्र कैलाश निवासी शंकर मार्केट लोहे की टंकी के पास कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल हाल निवासी टीन मार्केट रावली महदूद को एचएमटी होटल को जाने वाले रास्ते निकट डेंसो चौक से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी के आदेश पर नशा तस्करों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने में जुटी हरिद्वार पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस के मुताबिक गैंग लीडर सागर उर्फ गबरू को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ये सभी आरोपी गिरोह बनाकर नशा तस्करी कर रहे थे।

ठंड से बचाने के लिए नगर निगम की सराहनीय पहल, जरुतमंदों के लिए जलाए अलाव

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर बढ़ते शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम द्वारा सराहनीय पहल की गई है। नगरायुक्त नंदन कुमार ने शहरवासियों, विशेषकर जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों को शीत लहर से बचाव के लिए व्यापक व्यवस्थाएं कराते हुए ठंड से बचाव के लिए जहां अलाव की व्यवस्था करायी गई वहीं रैन बसेरों और गरम कंबलों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है।

उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया कि नगर आयुक्त नंदन कुमार द्वारा रैन बसेरों का निरीक्षण किए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के क्रम में नगर निगम द्वारा कुल 150 गर्म कंबलों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें रैन बसेरों में भिजवाया जा चुका है। वर्तमान में रैन बसेरों में गर्म कंबल एवं हीटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वहां ठहरने वाले लोगों को ठंड से राहत मिल सके। नगर निगम क्षेत्र में कुल तीन रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहर के 40 से अधिक स्थानों पर

अलाव जलवाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त नंदन कुमार IAS ने स्पष्ट किया कि विशेष रूप से मुख्य चौराहों एवं ऐसे स्थानों पर, जहां राहगीरों का अधिक ठहराव रहता है, वहां अलाव की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर नगर निगम हरिद्वार की महापौर किरण जैसल ने बताया कि नगर निगम सर्दी से बचाव के लिए लगातार प्रयासरत है तथा शीघ्र ही गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। नगर निगम द्वारा की जा रही यह पहल सर्दी के मौसम में जनहित एवं मानवीय संवेदना की दिशा में एक सकारात्मक और सराहनीय कदम है।

साध्वी प्राची ने हरिद्वार को अमृत क्षेत्र घोषित करने की उठाई मांग

पथ प्रवाह, हरिद्वार

हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने धर्मनगरी हरिद्वार को 'अमृत क्षेत्र' घोषित किए जाने की मांग करते हुए हरकी पैड़ी क्षेत्र की पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं के संरक्षण पर जोर दिया है। प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हरकी पैड़ी हिंदू समाज का अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है, जहां आस्था, परंपरा और धार्मिक नियमों का विशेष महत्व है। साध्वी प्राची ने कहा कि हरकी पैड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए गैर-

धर्मावलंबियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हरकी पैड़ी के 200 से 300 मीटर के दायरे को विशेष पवित्र क्षेत्र घोषित कर वहां धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप नियम लागू किए जाएं। इसके साथ ही गैर-हिंदुओं द्वारा संपत्ति खरीदने पर भी रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने अन्य धार्मिक स्थलों का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वेटिकन सिटी और मक्का-मदीना में विशेष धार्मिक नियम लागू हैं, उसी प्रकार हरिद्वार में भी पवित्रता बनाए रखने के लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। साध्वी प्राची ने नगर निगम द्वारा बनाए गए बायोलॉज और नियमों के सख्ती से पालन की भी मांग की।

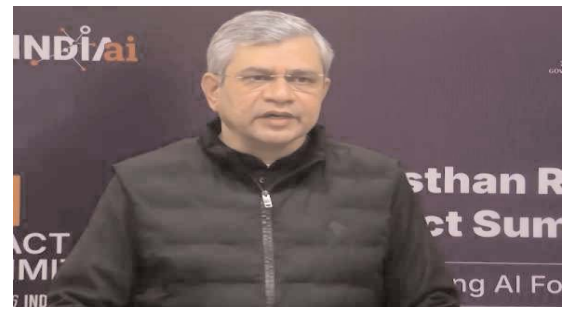

भारत में एआई को समावेशी, सुलभ और जनोपयोगी बनाने की दिशा में उठाये जा रहे हैं ठोस कदम: वैष्णव

जयपुर। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आने वाले समय में मानव जीवन का अभिन्न अंग बनेगा और हर व्यक्ति, हर घर तथा हर उद्यम तक इसकी पहुंच होगी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में एआई को समावेशी, सुलभ और जनोपयोगी बनाने की दिशा में ठोस एवं दूरदर्शी कदम उठाए जा रहे हैं। श्री वैष्णव ने आज यहां जेईसीसी में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि कम समय में भारत ने एआई मशीनों और तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और आज देश की एआई क्षमताएं विश्व स्तर पर चर्चित है। एआई कंप्यूट सुविधा को 'जन-जन' तक पहुंचाने के उद्देश्य से कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत देशभर में कम लागत पर उन्नत कंप्यूट संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एआई विकास के क्षेत्र में भारत आज विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल है। चीन, अमेरिका और भारत एआई डेवलपमेंट में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आईटी इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ताकत है और एआई के माध्यम से यह शक्ति और सुदृढ़ होगी। विशाल प्रतिभा, मजबूत डिजिटल

इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार आधारित इकोसिस्टम भारत को वैश्विक स्तर पर एआई क्षेत्र में नेतृत्व की ओर ले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से राजस्थान तकनीकी नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा और देश के युवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

स्मार्ट एवं डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के साथ होगा दिव्य और भव्य कुंभ आयोजनः विनय रोहिला

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

अगामी 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को दिव्य, भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किए जाने के लिए उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन विनय रोहिला ने किए जा रहे निर्माण कार्यों एवं की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की।

समीक्षा करते हुए उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने कहा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है कि आगामी 2027 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले को दिव्य, भव्य एवं स्मार्ट डिजिटल तकनीक के माध्यम से कुंभ मेले को सुव्यस्थित ढंग से आयोजित किया जाए। संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए सभी अधिकारी इसमें व्यक्तिगत रूप से संचालित निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं करे, जिससे कि कार्य समय से पूर्ण कराए जा सके। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला 2027 केवल एक धार्मिक आयोजन

नहीं बल्कि यह राज्य की प्रशासनिक क्षमता तकनीकी दक्षता एवं आपदा प्रबन्धन प्रणाली की एक ऐतिहासिक परीक्षा है। जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा,सुविधा एवं विश्वास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे विशाल आयोजन में बाढ़, अग्निकांड, भगदड़, स्वास्थ्य आपात स्थितिया, मौसम जनित आपदाएं, संचार व्यवधान तथा अफवाह जैसे चुनौतियां स्वाभाविक है इसलिए हमें किसी घटना के घटित होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पूर्व तैयारी आधारित, जोखिम केंद्रित तकनीक संचालित आपदा प्रबंधन मॉडल अपनाना होगा।

श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप बनाए योजना

उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन कुंभ का सबसे संवेदनशील पहलू है, श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के अनुरूप सेक्टरवार योजना, आवागमन, वैकल्पिक निकासी मार्ग तथा होल्डिंग एरिया विकसित किए जाए।उन्होंने कहा कि यातायात एवं परिवहन प्रबंधन के अंतर्गत रेलवे, रोडवेज एवं निजी वाहनों के लिए पृथक योजना हो तथा बाढ़ एवं जल प्रबंधन की दृष्टि से गंगा एवं घाट क्षेत्रों में जलस्तर की निरंतर निगरानी, मौसम विभाग से रियल टाइम समन्वय, चेतावनी प्रणाली तथा सुरक्षित स्थलों की पहचान, घाटों पर रेस्क्यू बोट, गोताखोर एवं लाइफ जैकेट की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में टेंट सिटी,अखाड़ों,विद्युत व्यवस्था एवं सामुदायिक रसोई क्षेत्रों में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाए साथ ही स्वास्थ्य एवं आपात चिकित्सा सेवाएं कुंभ की रीढ़ हैं।फील्ड हॉस्पिटल,मोबाइल मेडिकल यूनिट,मेडिकल पोस्ट एवं एंबुलेंस नेटवर्क पूरी तरह कार्यशील रहे।

विभागों ने दी किये जा रहे कार्यों की जानकारी

इस अवसर पर नगर निगम ,लोनिवि,राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वास्थ्य विभाग, एनएचएआई, सिंचाई विभाग ,पुलिस विभाग,जल संस्थान,जल निगम,विद्युत विभाग, खाद्य विभाग,जिला पूर्ति विभाग, परिवहन विभाग,एचआरडीए आदि विभागों द्वारा कुंभ मेले के लिए की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में अपने अपने विभागों से संबंधित कार्ययोजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने पीपीटी के माध्यम से कुंभ मेले में होने वाले कार्यों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

ये अधिकारी रहे बैठक में ?शामिल

बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्साधिकारी आर के सिंह, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, सीओ कुंभ बिपेंदर सिंह, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

शेयर बाजारों में लगातार दूसरी गिरावट, रिलायंस का शेयर 4.4 प्रतिशत लुढ़का

मुंबई। विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मुनाफावसूली के कारण मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गयी। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 376.28 अंक (0.44 प्रतिशत) टूटकर 85,063.34 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक 71.60 अंक यानी 0.27 फीसदी नीचे 26,178.70 अंक पर बंद हुआ।

टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट का शेयर 8.62 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी मुनाफावसूली का दबाव रहा और इसका शेयर 4.42 प्रतिशत टूटा।

मझौली कंपनियों के निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक में 0.06 फीसदी और छोटी कंपनियों के निफ्टी स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 0.22 प्रतिशत की गिरावट रही।

तेल एवं गैस, रसायन और मीडिया सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। स्वास्थ्य, फार्मा, आईटी और सार्वजनिक बैंकों के समूहों के सूचकांक हरे निशान में रहे।

एनएसई में कुल 3,237 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 1,889 के शेयरों में गिरावट और 1,238 में बढ़त रही। अन्य 110 कंपनियों के शेयर अंत में अपरिवर्तित बंद हुए।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 13 के शेयरों में गिरावट रही। ट्रेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा आईटीसी का शेयर 2.07 प्रतिशत और कोटक महिंद्रा बैंक का 2.02 प्रतिशत गिर गया। इंडिगो में 1.96 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक में 1.56, अडानी पोर्ट्स में 1.30, पावरग्रिड में 1.16 और इटरनल में 1.08 प्रतिशत की गिरावट रही।

जी राम जी योजना' बनेगी विकसित भारत की आधारशिलाः योगी

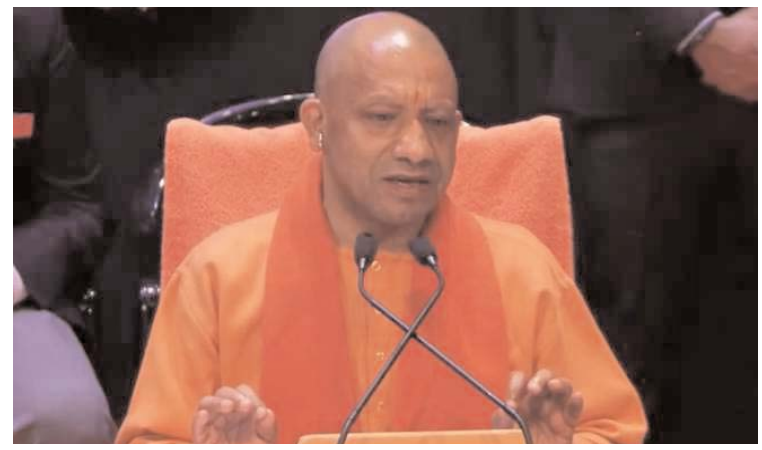

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसद में विकसित भारत को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया नया अधिनियम (जी राम जी योजना) देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक संसाधनों पर डकैती डालकर देश को बेरोजगारी की ओर धकेला, आज उन्हें अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन विकास से जुड़े सकारात्मक कदमों का समर्थन करने के बजाय भ्रष्टाचार के अपने पुराने कारनामों को छिपाने के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं।

योगी ने कहा कि जी राम जी योजना विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई तकनीक को जोड़ा जा रहा है, जिससे जल संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने मनरेगा पर कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन योजनाओं का ढोल पीटा जा रहा है, उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं रहा। हर जनपद से भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। किसानों को जरूरत के समय मजदूर नहीं मिलते थे और मजदूरों को काम के समय काम नहीं मिलता था।

उन्होंने बताया कि नए संशोधन के तहत योजना में कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। समय पर काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते की गारंटी भी होगी। किसानों की जरूरत को देखते हुए आवश्यक समय पर मनरेगा के कार्य स्थगित रखे जाएंगे। योगी ने कहा कि जो लोग केवल खोदने और भरने से लाभ उठाते थे, वही इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अब कार्यों को तकनीक से जोड़ा जाएगा, डिजिटल भुगतान होगा और रियल टाइम ऐप के माध्यम से निगरानी की जाएगी। योजना के अंतर्गत ऑडिट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए, जिनकी जांच चल रही है।

उन्होंने कहा कि इस योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 की रहेगी, जिससे उत्तर प्रदेश को करीब 17 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिल सकेगी। जिन राज्यों में श्रमिक वर्ग की संख्या अधिक है, उन्हें अधिक कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग 334 ए से हटाया गया अवैध अतिक्रमण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूर्व में ही सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रांतर्गत परिसंपत्तियों/ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 334ए पर अतिक्रमण हटाया गया। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सुरेश तोमर ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 ए पर सड़क किनारे सिंहद्वार से लक्सर एवं पुरकाजी आदि क्षेत्रों से अवैध रूप एवं बिना अनुमति के लगाए गए बड़े यूनीपोल एवं होर्डिंग को हटाया जा रहा है,इसके साथ ही सड़क किनारे लगाए फड़, ठेलियों एवं खोखे को भी हटाया जा रहा है, जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्ग आवागमन हेतु बाधित न हो सके।

स्वच्छता अभियान के एक महीना 19 दिन हुए पूरे, बुलंद हो रहा नारा, साफ स्वच्छ हो जनपद हमारा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ, स्वच्छ एवं सुंदर बनाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के मंगलवार को एक माह 19 दिन पूरे हो गए। निरंतर चल रहे सफाई अभियान का धरातल पर असर दिखने लगा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की इस सराहनीय पहल से समाजेसवी संगठन भी अभियान में जुड़ रहे हैं। बीएचईएल नगर प्रशासक संजय पवार ने अवगत कराया है कि बीएचईएल क्षेत्रांतर्गत पेंटागन मॉल के पास डिस्पेंसरी सेक्टर 6 क्षेत्र में भेल टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा कूड़ा उठाया गया साथ ही मध्य मार्ग,शिवालिक मार्ग एवं रानी राव पुल पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। अधिशासी अभियंता एनएचएआई अतुल शर्मा ने अवगत कराया है कि दूधधारी फ्लाईओवर शांतिकुंज से चंडी चौक फ्लाईओवर तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्रांतर्गत पर साफ सफाई का अभियान चलाया गया। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सुरेश तोमर ने अवगत कराया है कि हरिद्वार लक्सर मार्ग पर पदार्था राष्ट्रीय राजमार्ग

334 ए में सफाई का कार्य कराया गया। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग हरिद्वार दीपक वर्मा ने अवगत कराया है कि भूपतवाला एवं सिडकुल क्षेत्रांतर्गत फोर लाइन सड़क मार्ग की से साफ सफाई की गई साथ ही सड़क किनारे पड़े कचरे,मिट्टी को हटाया गया। खंड विकास अधिकारी खानपुर ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत गिद्दावली ,बालावाली, डुमनपुरी में साफ सफाई का कार्य कराया गया जिसमें लगभग 10 कुंतल कूड़ा एकत्रित किया गया। खंड विकास अधिकारी रुड़की ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत लाठरदेवा क्षेत्रांतर्गत साफ अभियान चलाया गया,जिसमें लगभग 6 कुंटल कूड़ा एकत्रित किया गया। जिला प्रशासन की स्वच्छता अभियान के लिए अपील की गई है कि गांव-गांव, घर- घर यह स्वच्छता का संदेश पहुंचाना है। जनपद को साफ स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान में सभी को मिलकर आगे आना है।

संपादकीय

कड़ाके की सर्दी और उत्तराखंड की परीक्षा

उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी एक बार फिर जनजीवन के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। पर्वतीय जिलों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर व घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। यह स्थिति केवल मौसम की मार नहीं, बल्कि प्रशासनिक तैयारी, सामाजिक संवेदनशीलता और स्वास्थ्य व्यवस्था की भी परीक्षा है।

राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों–चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग–में तापमान शून्य के आसपास पहुंच चुका है। कई स्थानों पर सड़कें बंद हैं, जिससे आवागमन और आपूर्ति प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में शीतलहर और कोहरा दैनिक गतिविधियों को बाधित कर रहे हैं। स्कूलों के समय में बदलाव और यातायात पर असर इस बात का संकेत है कि ठंड का असर व्यापक है।

सर्दी का सबसे गहरा प्रभाव कमजोर वर्गों पर पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे और बेघर लोग ठंड से सबसे अधिक जोखिम में हैं। सरकार द्वारा रैन बसेरे, अलाव और कंबल वितरण जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इनका प्रभाव तभी सार्थक होगा जब इनकी निगरानी निरंतर और निष्पक्ष हो। अक्सर देखने में आता है कि योजनाएं कागजों पर बेहतर दिखती हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय संवेदनशील है। श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएं और ठंड से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तैयारी, एंबुलेंस सेवाओं की उपलब्धता और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है।

यह सर्दी एक बड़ा संकेत भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के स्वरूप में आ रहे बदलाव भविष्य में और गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। इसलिए अब सर्दी को केवल मौसमी घटना मानने के बजाय दीर्घकालिक नीति और तैयारी का विषय बनाना होगा। उत्तराखंड की कड़ाके की सर्दी यह याद दिलाती है कि प्राकृतिक चुनौतियों से निपटने के लिए केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है।

आमजन में उम्मीद की लौ जलाने में कामयाब रही मोदी सरकार

मनोज कुमार अग्रवाल

आजादी के 77 साल में यदि भारत के विकास क्रम की समीक्षा की जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 वर्षों का कार्यकाल यकीनन पिछले साढ़े छह दशक पर भारी है। मोदी सरकार ने देश के विकास की एक नयी लकीर खींची है। नरेन्द्र मोदी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिये समर्पित रहा है। यह समय अनूठा, अद्भुत और अकल्पनीय है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व में मान, सम्मान और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा देश की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान की यात्रा है। इसमें एक ओर भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, देश का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है और भारत अब डिफेंस इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। वहीं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सम्मान का मंत्र दिया। उन्होंने इन्हीं चार स्तंभों के समग्र विकास से वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का मार्ग बताया।

प्रधानमंत्री जी की नीतियों और निर्णयों ने नये आत्मनिर्भर भारत निर्माण को गति दी है। 11 वर्ष पूर्व पूर्व पीएम मोदी ने संसद की सीढ़ियों को नमन करके जो संकल्प व्यक्त किये थे, उनमें उनकी भावी यात्रा के साथ नये भारत निर्माण के संकेत भी थे। उन्होंने निरंतर अपने संकल्पों की सिद्धि के साथ देश को आगे बढ़ाया है और राष्ट्र तथा समाज के उत्थान के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, भारत में नागरिकता कानून (सीएए) बनाने, तीन तलाक जैसे अमानवीय कानून को समाप्त करने, वक्फ संपत्ति का मुस्लिम समाज के कल्याण में उपयोग के लिए वक्फ संशोधन विधेयक कानून लाने जैसे निर्णय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से ही संभव हुए हैं। उनका दृढ़ संकल्प सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भी दिखाई दिया। बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत के सामर्थ्य को पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में बहनों के सामने आर्तोकयों ने उनका सिंदूर मिटाया था, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित कर दिया कि यह नया भारत है जो राष्ट्र के सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा और मानवता के लिए घर में घुसकर भी मारना जानता है। पीएम मोदी के कार्यकाल की यह समृद्ध यात्रा राष्ट्र की उमति, आधारभूत समस्याओं के निराकरण और वैश्विक छवि के उत्थान की रही है। देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क अम्र, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पका घर, हर घर में शौचालय, 15.6 करोड़ से अधिक भरों में नल से जल, 10 करोड़ से अधिक मरों में उज्वला योजना से गैस कनेक्शन और गांवों को रोशन किया है। उनके स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छता एवं साफ सफाई में जुट गया। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सचका विकास और सबका विश्वास का उद्घोष किया। उनकी नीतियों में अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की अवधारणा है। सबके स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए आयुष्मान भारत अभियान चलाया। इसमें 9 करोड़ से अधिक लोगों का मुफ्त उपचार हुआ है। सत्तर वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी निःशुल्क उपचार मिला है। 16 हजार से अधिक जन औषधि केन्द्रों से सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध करवाई है। कोरोना काल में देशवासियों को आपदा में अवसर का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण का संकल्प दिया और देशवासियों को स्वदेशी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई। इस भारतीय वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने भी स्वीकारा। उन्होंने श्रृंखलाबद्ध लोक एवं जन कल्याण कारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के समग्र विकास की समुचित व्यवस्था की। जनधन योजना से 55 करोड़ से अधिक लोगों को वित्तीय धारा से जोड़ा गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से गरीवों को 44 लाख करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। पीएम स्वनिधि और स्ट्रीट वेंडर से रेहड़ी-पटरी के व्यवसायियों को आधार दिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी, युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए, नई शिक्षा नीति के साथ 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास और 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप्स शुरू कर युवाओं को विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिये भागीदार बनाया है। मध्यप्रदेश ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को अमल में लाया और युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार तथा स्व-रोजगार के लिये अनंत संभावनाए विकसित की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 7.7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा से अप्रदाताओं को संबल मिला है। महिलाओं की सुरक्षा के उपाय, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। देशभर में लगभग 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

उमर-शरजील की जमानत का फैसला विवादों में

सनत जैन

उमर खालिद और शरजील इमाम से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों और आदेशों ने एक बार फिर भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन पर बहस को तेज कर दिया है। यह मामला केवल दो व्यक्तियों की जमानत का नही है।बल्कि उस व्यापक प्रश्न का है,जिसमे संविधान के अनुसार सरकार की आलोचना और विरोध को आम व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने वाला दिख रहा है।सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार और जांच एजेंसियों को सुरक्षा दे रहा है। जिसमें यूपीए के माध्यम से किसी भी नागरिक को किसी भी अवधि तक जेल में बंद रखा जा सके। विरोध की अभिव्यक्ति और आलोचना को किस हद तक अपराध की श्रेणी में रखकर सरकार और जांच एजेंसियां नागरिक अधिकारों के खिलाफ उपयोग में ला सकती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) नागरिकों को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। जबकि अनुच्छेद 19(1)(बी) शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा का अधिकार सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में अनेक बार स्पष्ट किया है।असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, सरकार के खिलाफ बोलना या विरोध करना राष्ट्र-विरोधी नहीं हो सकता है। किंतु उमर-शरजील मामले में कठोर धाराओं, विशेषकर यूएपीए जैसी कानूनों के प्रयोग कर 5 वर्ष से अधिक समय हो जाने के बाद भी उन्हें ना तो जमानत दी गई है। नाही जांच एजेंसी ने कोर्ट में चार्ज सीट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह सवाल खड़ा होता है। क्या आलोचना को साजिश और भाषण को हिंसा की मंशा मानने की प्रवृत्ति सरकार में बढ़ रही है। इसका असर सभी लोगों पर आम रूप से पड़ेगा। जमानत जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की कार्यवाही का एक तरह से अनुकरण कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय ने यह संकेत दिया है। सरकारी व्यवस्था के खिलाफ उग्र या असहज करने वाला भाषण अथवा अभिव्यक्ति स्वतः हिंसा के लिए उकसावा नहीं है। भाषण और वास्तविक हिंसा के बीच सीधा और स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर सरकार और जांच एजेंसियों का कठोर प्रहार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह टिप्पणी संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह संवैधानिक प्रभाव राज्य को चेतावनी देता है, कानून-व्यवस्था के नाम पर अधिकारों का अंधाधुंध दमन स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, यह सच है,अदालत ने पूरी तरह से राज्य की कार्रवाई को खारिज नहीं किया। बल्कि जांच प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए जमानत से इनकार किया है। जांच एजेंसी 5 साल से अधिक समय तक आरोपियों पर आरोप तय नहीं कर पाई। दोनों आरोपी 2020 से जेल में बंद हैं। इसका परिणाम यह हुआ, लंबी न्यायिक प्रक्रिया स्वयं एक दंड का रूप लेती दिखाई देती है। वर्षों तक जेल में रहना, बिना दोष सिद्ध हुए, मौलिक अधिकारों की भावना के विपरीत है। जिस संविधान की रक्षा करने का भार न्यायपालिका के ऊपर है।यदि वही संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करेगी, तो क्या होगा। इसे आसानी से समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर जो फैसला दिया है, उससे यही संदेश जाता है, सरकार के खिलाफ मुखर होना अब जोखिम भरा हो गया है, लोकतांत्रिक समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है।

उमर-शरजील प्रकरण से यह स्पष्ट होता है, भारतीय न्यायपालिका के लिए एक संवैधानिक रेखा खींचना जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णय को मान्य नहीं कर रहा है। संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जज मानने के लिए तैयार नहीं है। देश में हिंसक और नफरत का वातावरण बढ़ता जा रहा है। न्यायालय द्वारा जिस तरह का न्याय किया जा रहा है। वह भी अब विवादों में आने लगा है। एक ओर वास्तविक हिंसा और आतंक से सख्ती से निपटाने की जरूरत है। वहां पर यदि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सरकार के खिलाफ विरोध करने पर सरकार उत्पीड़न करती है। यदि न्यायपालिका का भी उत्पीड़न भी इसमें शामिल हो जाए। ऐसी स्थिति में संविधान और लोकतंत्र के रहते हुए मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का कोई मायना नहीं रह जाएगा। दूसरी ओर विचार, भाषण और विरोध को अपराध की श्रेणी में लाने से आदमी अभिव्यक्ति से डरने लग जाएगा। यदि न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों की ढाल को कमजोर करेगी, तो लोकतंत्र केवल कागजों पर औपचारिक रूप मे रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला हमें याद दिलाता है। संविधान केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि असहमति रखने वाले नागरिकों के लिए भी समान रूप से लागू है। सरकारों का आना-जाना तय है। यदि विरोध का अधिकार ही खत्म हो गया, तो लोकतंत्र समाप्त होते देर नहीं लगेगी। लोकतंत्र खत्म होगा तो तानाशाही स्थापित होगी। 1975 में घोषित रूप से आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसमें भी जेल में बंद रखने की अधिकतम अवधि तय थी। सात आरोपियों को 2020 से जेल में बंद करके रखा गया है। उनके आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 1 साल तक जमानत अर्जी दायर करने पर भी रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में अब संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का भी कोई मायना नहीं रह गया है। इस मामले में न्याय पालिका की भूमिका को लेकर आम लोगों में निराशा और गुस्सा देखने और सुनने को मिल रहे हैं। यह स्थिति भारत के लिए चिंताजनक है।

वेनेजुएला संकटः अमेरिकी निरंकुशता और वैश्विक कानूनों का हनन

ललित गर्ग

वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में नियम-कानूनों से संचालित होती है या फिर ताकतवर राष्ट्रों की इच्छा ही वैश्विक न्याय का नया मानदंड बन चुकी है। निश्चित तौर पर वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला महाशक्तियों की निरंकुशता को दर्शा ही रहा है, यह वैश्विक कानूनों का अतिक्रमण भी है, जो अमेरिकी दादागिरी का त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण संकेत है, वह केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि समूची दुनिया के लिये एक खतरनाक मिसाल है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, उससे जुड़े कूटनीतिक, राजनीतिक और अन्तराष्ट्रीय कानून संबंधी सवाल जो खड़े हुए ही हैं, पर अमेरिका को हस्तक्षेप का अवसर देने के लिये मादुरो की नीतियां भी चर्चा में आई हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की वजहें हो सकती है, लेकिन ट्रंप को यह तो सुनिश्चित करना ही होगा कि यह राष्ट्र अस्थिरता का अड्डा न बन जाये।

अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को वैश्विक शांति का मसीहा घोषित करते नहीं थकते, लेकिन उनकी नीतियां और कार्रवाइयाँ बार-बार युद्ध, हस्तक्षेप और सत्ता परिवर्तन की मानसिकता को उजागर करती हैं। यह वही अमेरिका है जो एक ओर लोकतंत्र, मानवाधिकार और संप्रभुता की दुहाई देता है, तो दूसरी ओर एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशंका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशों में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। इस तरह की दोहरी नीतियां केवल विडंबनापूर्ण नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के लिये घातक है। वेनेजुएला संकट को केवल मादुरो बनाम अमेरिका के टकराव के रूप में देखना वास्तविकता को सरलीकृत करना होगा। इसमें संदेह नहीं कि मादुरो सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, दमनकारी नीतियों, चुनावी अनियमितताओं और मानवाधिकार हनन जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। लाखों वेनेजुएलावासी देश छोड़ने को मजबूर हुए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जनता त्रस्त हुई। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी देश की आंतरिक विफलताओं को आधार बनाकर बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को वैध ठहराना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आत्मा के विरुद्ध है। यदि यही मापदंड हो, तो दुनिया के अनेक देशों में बाहरी हस्तक्षेप का अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है।

दरअसल, वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की असली चिंता न लोकतंत्र है और न ही मानवाधिकार, बल्कि वहां के विशाल तेल भंडार हैं। वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा देश है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी भूख कोई नई बात नहीं है। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान इसके उदाहरण हैं, जहां 'लोकतंत्र स्थापना' के नाम पर हस्तक्षेप हुआ, लेकिन परिणामस्वरूप अस्थिरता, गृहयुद्ध और मानवीय संकट ही पैदा हुआ। ट्रंप का यह बयान कि मादुरो को पकड़ने के अभियान का खर्च वेनेजुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, इस पूरे घटनाक्रम की मंशा को बेनकाब करता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि यह कार्रवाई न्याय या नैतिकता से नहीं, बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण की साम्राज्यवादी सोच से प्रेरित है। किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह दावा करना उपनिवेशवादी मानसिकता का आधुनिक संस्करण है। इस अमेरिकी कार्रवाई के भू-राजनीतिक परिणाम भी गहरे और दूरगामी होंगे। रूस और चीन ने इसे नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये गंभीर खतरा बताया है। मादुरो के आलोचक रहे कुछ अमेरिकी सहयोगी देश भी अब खुलकर चिंता जता रहे हैं। यह संकट वैश्विक ध्रुवीकरण को और तेज कर सकता है। विशेष रूप से चीन को इस घटनाक्रम से अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, विशेषकर ताइवान पर अमेरिकी आलोचना को कमजोर करने का अवसर मिल सकता है। यदि अमेरिका स्वयं संप्रभुता का उल्लंघन करता है, तो वह दूसरों को किस नैतिक आधार पर संयम की सलाह देगा? वेनेजुएला संकट का एक और चिंताजनक पहलू वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है। तेल उत्पादन और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। तेल कीमतों में उछाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर सकता है, विशेषकर विकासशील देशों को। भारत जैसे देशों के लिये यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, जहां ऊर्जा आयात पर निर्भरता अधिक है। यही कारण है कि भारत ने इस घटनाक्रम पर संतुलित रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से संवाद व कूटनीतिक समाधान की वकालत की है।

भारत का यह दृष्टिकोण न केवल व्यावहारिक है, बल्कि नैतिक रूप से भी अधिक जिम्मेदार है। युद्ध और हस्तक्षेप किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है कि इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका को अंततः अपमानजनक विदाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वे देश आज भी स्थिरता और शांति से कोसों दूर हैं। युद्ध शुरू करना भले आसान हो, लेकिन शांति और सुशासन स्थापित करना अत्यंत कठिन होता है-यह सत्य अमेरिका बार-बार भूलता रहा है। ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह स्वयं को शांति का अग्रदूत बताता है, लेकिन उसकी हर बड़ी विदेश नीति पहल टकराव और दबाव की राजनीति पर आधारित दिखती है। यह दोहरी मानसिकता न केवल अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रासंगिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। यदि शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों के अनुसार नियम तोड़ने लगें, तो वैश्विक व्यवस्था अराजकता की ओर बढ़ेगी।

अंकिता की माता-पिता की भावनाओं के अनुरूप होगा अगला निर्णय : मुख्यमंत्री पुष्कर धामी

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इस दिशा में सरकार ने पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया है। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए महिला अधिकारी रेणुका देवी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया था। एसआईटी ने मामले के प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच की, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की सशक्त और प्रभावी न्यायालयीय पैरवी के चलते तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच पर न केवल निचली अदालत, बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया है। यह तथ्य जांच की निष्पक्षता और मजबूती को दर्शाता है तथा सरकार के प्रयासों पर न्यायपालिका की मुहर लगाता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि वर्तमान में किसी कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रदेश में अनावश्यक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता से अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है और दोषियों को कठोर सजा मिल चुकी है।

सीबीआई जांच के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूरे प्रदेश की जनता की भावनाएं बेटी अंकिता के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस दुखद घटना से सबसे अधिक प्रभावित उसके माता-पिता हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अंकिता के माता-पिता से संवाद करेंगे और उनकी भावनाओं, पीड़ा एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दोहराया कि राज्य सरकार बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस दिशा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।

एक नजर

प्रॉपर्टी डीलर के बंद मकान में चोरी प्रकरण में मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कनखल क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर के बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए जांच शुरू कर दी है। महेंद्र सिंह नेगी निवासी अजितेश विहार, राजा गार्डन जगजीतपुर ने पुलिस को बताया कि वह 25 दिसंबर को अपने परिवार के साथ पौड़ी गढ़वाल जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में आयोजित भागवत कथा में शामिल होने गए थे। घर पर ताला लगा हुआ था। 31 दिसंबर को उनके निजी सुरक्षा अधिकारी प्रवीन कुमार ने फोन कर सूचना दी कि मकान का पिछला दरवाजा खुला हुआ है, जिससे चोरी की आशंका जताई गई।

सूचना मिलते ही महेंद्र सिंह नेगी परिवार सहित हरिद्वार पहुंचे। घर के भीतर प्रवेश करने पर देखा कि पिछला गेट खुला था और अलमारियों से नकदी तथा सोने के जेवर गायब थे। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों की दिशा बदल दी थी और डीवीआर भी उखाड़ ले गए थे। कनखल थाना प्रभारी मनोहर सिंह रावत ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

बेहरमी से की मारपीट, चार युवकों पर मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पहले युवक को कार से टक्कर मारी गई और जब वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया तो उस पर पंच से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक के सिर में 17 टांके आए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के पिता जितेंद्र कुमार निवासी कड़च्छ मोहल्ला ज्वालापुर ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र अनुराग 30 दिसंबर की शाम करीब 7:40 बजे जटवाड़ा पुल की ओर से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उसके दोस्त दानिश का फोन आया, जिसने उसकी लोकेशन पूछी। अनुराग ने घर जाने की बात कहकर फोन काट दिया। कुछ समय बाद जब परिजनों ने अनुराग से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल फोन बंद मिला। अनहोनी की आशंका पर परिजन तलाश करते हुए डॉ. नारंग के क्लीनिक पहुंचे, जहां पता चला कि अनुराग के साथ मारपीट की गई है और वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में भर्ती है। आरोप लगाया कि शाहनूर, समोईल, दानिश और शोएब उर्फ आलू ने मिलकर पहले कार से टक्कर मारी और फिर पंच से सिर पर हमला किया। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली में धुंध-धुएं की चादर, एक्यूआई 'खराब'

नयी दिल्ली।नयी दिल्ली में मंगलवार को धुंध और धुएं (स्मॉग) की घनी परत छायी रही और शहर के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी रही।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 288 दर्ज किया गया, जो इसे 'खराब' श्रेणी में रखता है। कई गहन प्रदूषण वाले क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति और भी खराब रही, जिनमें आनंद विहार (343), आरके पुरम (324), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (313), द्वारका (307), अशोक विहार (302) और आईटीओ (286) शामिल हैं। अधिकांश क्षेत्रों में हवा जहां अस्वास्थ्यकर रही, वहीं कुछ स्थानों पर तुलनात्मक रूप से बेहतर 'मध्यम' श्रेणी दर्ज की गयी। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, बवाना में एक्यूआई 194 और आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में 185 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गयी और हवाई और सड़क यातायात बाधित हुआ।दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण तड़के विमानों के संचालन के लिए 'कैट तृतीय' प्रक्रिया लागू की गयी। दिल्ली एयरपोर्ट ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि हालांकि कैट तृतीय स्थितियों के तहत विमानों का आगमन और प्रस्थान जारी है, लेकिन कुछ उड़ानों में देरी या व्यवधान हो सकता है। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ानों की ताज़ा जानकारी के लिए अपनी संबंधित एयरलाइन कंपनियों से संपर्क करें। इससे पहले, भारत मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई क्षेत्रों के लिए 'घने' से 'बहुत घने' कोहरे का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने दृश्यता में गिरावट के कारण सड़क, रेल और हवाई यात्रा में व्यवधान आने का अनुमान जताया है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सरकार सख्त, सुरक्षा और संरक्षण दोनों पर समान जोर: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसके नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी, ठोस एवं समन्वित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने भालू, गुलदार, बाघ और हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने तथा वन विभाग और जिला प्रशासन के बीच संयुक्त निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखने पर जोर दिया। साथ ही प्रभावित गांवों में सोलर फेंसिंग, बायो-फेंसिंग, हनी-बी फेंसिंग, वॉच टावर जैसे सुरक्षा उपाय अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हाथी और बाघ कॉरिडोर सहित सभी वन्यजीव कॉरिडोरों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। वन्यजीव आवागमन मार्गों पर अंडरपास, ओवरपास और एनिमल पास की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वन्यजीव समन्वय समितियों को सक्रिय रखने, हॉट-स्पॉट मैपिंग शीघ्र पूरी करने और स्कूलों, आंगनबाड़ियों, जलस्रोतों व पैदल मार्गों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया।

बैठक में वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े 9 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जबकि संरक्षित क्षेत्रों की 10 किमी परिधि में उपखनिज चुगान से जुड़े 22 प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजने का निर्णय लिया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लिए गए निर्णय मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगे।

बैठक में विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

एसएसपी मंजूनाथ की टीम ने 12 घंटे में मर्डर केस सुलझाया, आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हल्द्वानी। कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र के मानपुर उत्तर में हुई जघन्य हत्या की घटना का नैनीताल पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और उसके पुत्र को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी दोनाली बंदूक और एक अवैध पिस्टल सहित कारतूस भी बरामद किए हैं। घटना दिनांक 4 जनवरी 2026 की रात्रि वार्ड संख्या-55 मानपुर उत्तर, हल्द्वानी की है। वादी पीयूष लोहनी पुत्र कैलाश चन्द्र लोहनी निवासी सी-66 जज फार्म मुखानी, हल्द्वानी की तहरीर पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर संख्या 07/2026 धारा 103(1), 352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित अनावरण एवं गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल के मार्गदर्शन तथा एएसपी/सीओ हल्द्वानी-लालकुआं दीपशिखा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए। सीसीटीवी फुटेज व सुरागरसी-

पतारसी के आधार पर पुलिस ने नामजद अभियुक्त अमित बिष्ट पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी मानपुर उत्तर वार्ड-55, हल्द्वानी को मात्र चार घंटे में गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी दोनाली बंदूक बरामद हुई। जांच में उसके पुत्र जय बिष्ट उम्र 19 वर्ष की संलिप्तता सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया। जय बिष्ट की तलाशी से एक पिस्टल व चार जिंदा कारतूस (.25 बोर) बरामद हुए, जिस पर एफआईआर संख्या 08/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण पुराना आपसी विवाद है। दोनों आरोपियों को बरामद असलहों सहित न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता सहित उप निरीक्षक रोहताश सिंह सागर, भूपेन्द्र सिंह मेहता, मनोज कुमार, गौरव जोशी, अनिल कुमार तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

एक नजर

रोजगार की तलाश में निकले युवक का अपहरण

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रोजगार की तलाश में घर से निकले युवक के लापता होने का मामला अब अपहरण में दर्ज कर लिया गया है। चमोली से ट्रांसफर होकर आई जीरो एफआईआर को हरिद्वार पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक पिछले कई महीनों से लापता है और उसका अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। सीमा देवी निवासी पाटी मसोली तहसील पोखरी जनपद चमोली ने पुलिस को बताया कि उनके पति अशोक सिंह नेगी (36) सितंबर 2024 में रोजगार के सिलसिले में तुंगनाथ गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में उन्होंने फोन कर बताया कि वह नौकरी की तलाश में हरिद्वार जा रहे हैं। 19 अक्टूबर 2024 को अशोक सिंह नेगी का अंतिम बार फोन आया, जिसमें उन्होंने हरिद्वार से जयपुर (राजस्थान) जाने की बात कही थी। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद है। परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि चमोली से ट्रांसफर होकर आई जीरो एफआईआर को अपहरण की धारा में दर्ज कर लिया गया है। युवक की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है।

कनखल पुलिस ने युवक को चाकू संग दबोचा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कनखल पुलिस ने सोमवार देर रात गश्त के दौरान एक युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष मनोहर सिंह रावत ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान निर्मल फार्म हाउस के पीछे एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह घबराने लगा, जिस पर उसे रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक अवैध चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम रवि निवासी मिशनपुर कनखल बताया।

ट्रक की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत

पथ प्रवाह, हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र में हाइवे पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से डाक विभाग के एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक का पहिया युवक के सिर के ऊपर से निकल गया। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमानंद अस्पताल के सामने पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा और ट्रक का पहिया उसके सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मृतक की पहचान वैभव कुमार (24) पुत्र विसंबर प्रसाद निवासी न्यू आदेश नगर, रुड़की के रूप में हुई है। वैभव हरिद्वार डाकघर में तैनात थे। वह मंगलवार सुबह रुड़की से मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहे थे। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भाई बहन पर चाकू से हमला, पुलिस कर रही आरोपी तलाश

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र में सिलाई सेंटर के बाहर खड़े होने से मना करने पर दो युवकों ने भाई-बहन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आयान पुत्र निसार निवासी तिरूपति कॉलोनी सलेमपुर ने पुलिस को बताया कि उनके घर में सिलाई सेंटर संचालित है। आए दिन कुछ युवक वहां खड़े होकर शोरगुल करते थे।

चार जनवरी को उसके भाई ने युवकों को वहां खड़े होने से मना किया, जिस पर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि आदित्य और चिंटू नाम के युवकों ने उसके भाई पर चाकू से छह बार वार किए। शोर सुनकर जब उसकी बहन भाई को बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसके हाथ पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। घायलों का अस्पताल में उपचार कराया गया। इसके बाद सोमवार को कोतवाली में तहरीर दी गई। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

उत्तरकाशी पुलिस का अभियान तेज, तीन फरार वारण्टी दबोचे

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तरकाशी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने तीन वारण्टियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशों के क्रम में की गई। पुलिस टीम ने न्यायालय से जारी विभिन्न वादों में वांछित अभियुक्तों की तलाश करते हुए वाद संख्या 598/2024 (एनडीपीएस एक्ट), वाद संख्या 380/2024 (एनआई एक्ट) एवं वाद संख्या 207/2024 के तहत तीन वारण्टियों को गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्तों को 6 जनवरी 2026 को पकड़ा गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक जगत सिंह, हेड कांस्टेबल शिव कुमार, कांस्टेबल सुनील जयाडा, दीपक चौहान और नीरज रावत शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

पश्चिम रेलवे का रेलवन ऐप अभियान: डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा, अनारक्षित टिकट पर 3% छूट व कैशबैक

अहमदाबाद। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों को रेलवन (RailOne) ऐप के माध्यम से डिजिटल, त्वरित एवं कैशलेस टिकटिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रचार अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है। रेलवन ऐप एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यात्री आरक्षित टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट बुकिंग एवं प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेनों की रियल टाइम जानकारी, ग्राहक सहायता आदि जैसी रेलवे की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टिकट बुकिंग स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ तथा संबंधित पर्यवेक्षकों को रेलवन ऐप की विशेषताओं के बारे में संवेदनशील किया गया है, ताकि वे यात्रियों को प्रभावी रूप से मार्गदर्शन एवं प्रेरित कर सकें। वाणिज्यिक पर्यवेक्षक एवं टिकट चेकिंग स्टाफ स्टेशनों पर सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चला रहे हैं, जिनके माध्यम से ऐप की उपयोगिता एवं सरलता को उजागर किया जा रहा है। सार्वजनिक जागरूकता को और अधिक बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर पोस्टर एवं पर्चे प्रदर्शित एवं वितरित किए जा रहे हैं, प्रमुख स्टेशनों पर विशेष सहायता काउंटर स्थापित किए गए हैं तथा जन उद्घोषणा (पीए) प्रणाली और पश्चिम रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित घोषणाएँ की जा रही हैं। अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को 3% की छूट प्रदान की जाएगी, जो 14 जनवरी, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगी। टिकटिंग के अतिरिक्त, रेलवन ऐप पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं में ट्रेन सर्च, पीएनआर स्थिति, कोच पोजिशन, ट्रैक योर ट्रेन, ऑर्डर योर फूड, रिफंड दर्ज करना, रेल मदद तथा गो टू वेव्स शामिल हैं। वर्तमान में यूटीएस ऐप का उपयोग कर रहे यात्रियों को भारतीय रेल के ऑल-इन-वन मोबाइल एप्लिकेशन रेलवन पर सहज रूप से स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे एक ही उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग जारी रखने के साथ-साथ अनेक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठा सकें। मौजूदा यूटीएस उपयोगकर्ता प्रदान किए गए इमेज फ्लोचार्ट में दर्शाई गई सरल चरणबद्ध माइग्रेशन प्रक्रिया का पालन करके अपने खातों को रेलवन ऐप में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स का स्थानांतरण संभव हो सकेगा और बिना किसी व्यवधान के सेवाओं का निरंतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

रेलवन ऐप तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, एंड्रॉयड तथा द्वह्स दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए त्त्क्र कोड स्कैनर स्टेशनों पर तथा पश्चिम रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रचारित किए जा रहे हैं, जिससे यात्री ऐप तक तुरंत पहुँच प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों के साथ-साथ 139 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर कार्यरत कर्मियों को भी रेलवन ऐप से संबंधित यात्रियों के प्रश्नों का समाधान करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से आंशिक राहत, दो मामलों में गिरफ्तारी पर रोक

पथ प्रवाह, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून जनपदों में दर्ज चार आपराधिक मुकदमों में से दो मामलों में सुनवाई करते हुए उन्हें फौरी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने बहादराबाद (हरिद्वार) और डालनवाला (देहरादून) थाने में दर्ज मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और मुकदमा दर्ज कराने वाले पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा और बहादराबाद थाने तथा देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना और डालनवाला कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोप है कि दोनों ने भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर ऑडियो-वीडियो वायरल किए। याचिकाकर्ता सुरेश राठौर की ओर से हाईकोर्ट में दो मुकदमों को चुनौती देते हुए कहा गया कि उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार नहीं किया है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए तथा मुकदमे निरस्त किए जाएं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दो मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस प्रकरण में शिकायतकर्ता दुष्यंत गौतम, धर्मेंद्र कुमार, संचित कुमार और आरती गौड़ को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। यह मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें अभिनेत्री उर्मिला सनावर द्वारा कुछ ऑडियो और वीडियो जारी किए गए थे। इन ऑडियो में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत अन्य लोगों के नाम सामने आने के बाद उनके द्वारा अलग-अलग थानों में छवि धूमिल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

शराब के नशे में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, पुलिस ने सुरक्षित उतारा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में मंगलवार को उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर की ऊंचाई पर पहुंचकर युवक इस कदर लापरवाह नजर आया कि वह लड़खड़ाकर टावर के भीतर ही गिर पड़ा। गनीमत रही कि युवक टावर से बाहर की ओर नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। टावर पर चढ़ने वाला युवक 27 वर्षीय ललित, धनपुरा गांव का ही निवासी बताया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक टावर के शीर्ष पर नशे की हालत में झूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। काफी देर तक चले रेस्क्यू प्रयासों के बाद युवक आखिरकार टावर से नीचे उतर आया। पुलिस के अनुसार युवक परिवार से

अनबन के चलते नाराज था और इसी आवेश में उसने खतरनाक कदम उठा लिया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। गौरतलब है कि करीब दस दिन पहले भी इसी मोबाइल टावर पर एक युवक नशे की हालत में चढ़ गया था। एक ही स्थान पर बार-बार इस तरह की घटनाएं सामने आने से सुरक्षा इंतजामों और पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से टावर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

वैभव सूर्यवंशी ने पंत का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे तेज भारतीय यूथ वनडे अर्धशतक बनाया

बेनोनी। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को विलोमूर पार्क में दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे के दौरान यूथ वनडे इंटरनेशनल में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज़ फिफ्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

रेगुलर कप्तान आयुष म्हात्रे की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी करते हुए, 14 साल के सूर्यवंशी ने पावर-हिटिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ़ 15 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया, जिससे उन्होंने सीनियर भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के पिछले भारतीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 18 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। युवा ओपनर आखिरकार 24 गेंदों पर शानदार 68 रन बनाकर आउट हो गए, इस पारी में क्लीन

स्ट्राइकिंग का बोलबाला था। उन्होंने 10 छक्के और सिर्फ़ एक चौका लगाया, जिसमें से 64 रन बाउंड्री से आए, जिससे साउथ अफ्रीकी गेंदबाज़ों को उन्हें रोकने में मुश्किल हुई। इससे पहले, साउथ अफ्रीका अंडर19 ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 49.3 ओवर में 245 रन पर आउट हो गई। बाद में बारिश की रुकावट के कारण बदले हुए हालात में भारत का टारगेट 27 ओवर में 174 रन कर दिया गया। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आक्रामक शुरुआत की, जिसमें ओपनर एरॉन जॉर्ज और सूर्यवंशी ने मेजबान टीम पर अटैक किया। दोनों ने सिर्फ़ 4.1 ओवर में टीम का पचास रन पूरा किया। जॉर्ज सबसे पहले आउट हुए, उन्होंने 19 गेंदों पर 20 रन बनाए, और भारत का स्कोर 6.1 ओवर में एक विकेट पर 67 रन था। सूर्यवंशी ने अपना अटैक जारी रखा, लेकिन 8.1 ओवर में माइकल क्रुइसकैंप ने उन्हें आउट कर दिया, और तब भारत का स्कोर 10 ओवर में दो विकेट पर 103 रन था। इसके बाद, वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने लक्ष्य का पीछा आसानी से खत्म किया। त्रिवेदी 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कुंडू ने नाबाद 48 रन बनाकर पारी को संभाला और भारत ने बिना किसी और नुकसान के जीत हासिल कर ली। साउथ अफ्रीका अंडर19 के लिए, क्रुइसकैंप सबसे असरदार बॉलर रहे, उन्होंने दोनों भारतीय विकेट लिए और छह ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए।

रेलवे स्टेशनों पर अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त आईजी, 6 माह में 200 मोबाइल बरामद

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उत्तराखंड में रेलवे स्टेशनों पर अपराध नियंत्रण, यात्रियों की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक (रेलवेज) उत्तराखंड मुख्तार मोहसिन ने मंगलवार को जीआरपी मुख्यालय हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने थानावार अपराधों की प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया। बैठक के दौरान आईजी रेलवेज ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपकर जीआरपी की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया।

पुलिस लाइन जीआरपी के निरीक्षण के बाद रानीपुर स्थित जीआरपी मुख्यालय सभागार में आयोजित बैठक में आईजी मुख्तार मोहसिन ने बताया कि बीते छह माह में उत्तराखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से चोरी और गुम हुए कुल 200 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया है। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 36 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि मोबाइल बरामदगी अभियान में सभी जीआरपी थानों और जीआरपी एसओजी टीम ने एकजुट होकर कार्य किया। सर्विलांस, सीईआईआर पोर्टल और मैन्युअल तकनीकी प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों से मोबाइल फोन बरामद किए गए।

आईजी रेलवेज ने थानावार अपराध समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि रेल यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित अभियोगों के शीघ्र अनावरण, अभियोगों से संबंधित संपत्ति की शत-प्रतिशत बरामदगी और विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया।

चोरी, जहरखुरानी और चेन स्नैचिंग पर सख्त रुख

आईजी मुख्तार मोहसिन ने चोरी, लूट, चेन स्नैचिंग और जहरखुरानी जैसी घटनाओं के मामलों में अनावरण और बरामदगी प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रेनों में एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की रोटेशन के आधार पर तैनाती, लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण और पुराने मामलों की न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने को कहा।

इसके साथ ही उन्होंने शराब पीकर ट्रेन में यात्रा करने वालों के खिलाफ चालान कार्रवाई तेज करने, अज्ञात व्यक्तियों के रन ओवर मामलों में पहचान के प्रयास करने और ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित कर आमजन को रेल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

मानव तस्करी और त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता

आईजी रेलवेज ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ समन्वय बनाकर रेलवे स्टेशनों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर बीडीएस और श्वान दल के माध्यम से सघन जांच के आदेश भी जारी किए गए।

उन्होंने सभी पोर्टलों को अपडेट रखने, कार्मिकों को पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण देने तथा उत्तराखंड पुलिस एप, गौरा शक्ति एप, जीआरपी हेल्पलाइन और 1090, 1930, 182, 112 एवं सीईआईआर पोर्टल के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए, ताकि आमजन को त्वरित सहायता मिल सके।

बैठक में एसपी जीआरपी अरुणा भारती, एसपी क्राइम हरिद्वार जितेंद्र मेहरा, एसपी सिटी अभय सिंह, स्टेशन अधीक्षक दिनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए गंगा सभा अध्यक्ष ने दिलायी शपथ

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से हरिद्वार में गंगा सभा द्वारा सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम जी द्वारा सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा से जुड़ा सामाजिक दायित्व है। शपथ के माध्यम से आमजन को यह संकल्प दिलाया गया कि वे यातायात नियमों का पालन करेंगे, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चलाएंगे, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे, तेज गति एवं लापरवाही से वाहन नहीं चलाएंगे तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही, अपने परिवार, समाज एवं संपर्क में आने वाले लोगों को भी सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवहार के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में गंगा सभा के स्वागत मंत्री डॉ. सिद्धार्थ चक्रपाणि, सचिव शैलेश गौतम, सचिव उज्ज्वल पंडित, तथा तीर्थ पुरोहितगण हिमांशु वशिष्ठ, राजकुमार झा, अमित झा एवं वंश वशिष्ठ विशेष रूप से उपस्थित रहे। परिवहन विभाग की ओर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) निखिल शर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा एवं परिवहन कर अधिकारी वरुणा सैनी ने सहभागिता करते हुए सड़क सुरक्षा माह के महत्व पर प्रकाश डाला तथा नागरिकों से यातायात नियमों के पालन में सक्रिय सहयोग की अपील की।

सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने अपर मुख्य अधिकारी और ईओ का एक दिन का वेतन रोका

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनता की समस्या को त्वरित निराकरण करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में लक्सर के तहसील सभागार में तहसील दिवस सम्पन्न हुआ। जिसमें फरियादियों द्वारा करीब 65 समस्याएं एवं मांग दर्ज कराई गई, जिसमें से 32 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा अन्य समस्याओं को निस्तारित कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये।

तहसील दिवस में मुख्यतः राजस्व विभाग, चकबन्दी, अतिक्रमण, जल भराव,कब्जा तथा नालों की सफाई आदि से सम्बन्धित थीं। आयोजित तहसील दिवस में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तहसील दिवस में जो भी समस्याएं क्षेत्रीय जनता द्वारा दर्ज कराई गई है उनका समयबृद्धता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता एवं ढिलाई नहीं बरतनी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि जनपद वासियों की समस्याओं का तहसील दिवस के अवसर पर ही निराकरण किया जाए ताकि जनपद वासियों को अपनी समस्याओं को लेकर अनावश्यक कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने उपजिलाधिकारी एवं पटवारी एवं लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए भूमि की पैमाइश की जाए पैमाइश करते हुए वस्तु स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो हस्तान्तरित की जा रही शिकायतों का संज्ञान लेते हए सभी शिकायतें को एक सप्ताह में निस्तारण करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि लक्सर तहसील दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें अतिक्रमण और कब्जे को लेकर आई है जिसको लेकर पटवारी, कानूनगो और अधिकारियों से कहा कि जो भी अनुरोधकर्ता अपनी शिकायत लेकर आते हैं, उनकी शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता से अवश्य होना चाहिये, उन्होंने सभी अधिकारियों को मुसतैदी से कार्य करने के निर्देश दिए, जो कार्य नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

तहसील दिवस में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के उपस्थित न होने पर उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। लक्सर क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक न पाए जाने पर गहरी नाराजी व्यक्त करते हुए ईओ नगर पालिका का भी एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

तहसील दिवस के दौरान अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान,उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल, तहसीलदार शुभांगी आदि अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

एसआईआर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया , चुनाव आयोग तथा भाजपा मतदाताओं के उत्पीड़न के दोषी :ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 'अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक' तरीके से करा रहे हैं। उन्होंने गंगासागर से लौटने पर पत्रकारों से बात करते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया 'गलत और मनमाने' तरीके से चलाई जा रही है। सुश्री बनर्जी ने कहा, 'आयोग सब गलत कर रहा है। जीवित लोगों को मृत दिखाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाइप लगाये बुजुर्ग लोगों को सुनवाई में घसीटा जा रहा है। पूरी प्रक्रिया एक तमाशा है। '

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'कुछ ऐप्स भाजपा की आईटी सेल की मदद से विकसित किये गये हैं। यह पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। यह जारी नहीं रह सकता।' मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तीसरी बार पत्र लिखकर एसआईआर में अनियमितताओं का मामला उठाया है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया और दावा किया कि प्रशासनिक संशोधन की आड़ में लोगों के मतदान के अधिकार छीने जा रहे हैं।

सुश्री बनर्जी की ये टिप्पणियां सोमवार को गंगासागर से की गई उनकी तीखी आलोचना के बाद आई हैं, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहारा लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया पर्याप्त तैयारी के बिना चलाई गयी, जिससे आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सुश्री बनर्जी स्वयं एक बेहतर अधिवक्ता हैं। उन्होंने सोमवार को कहा था, 'हम कानून की मदद ले रहे हैं। अदालत कल खुलेगी और हम अदालत में जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मैं उच्चतम न्यायालय जाने और जनता की ओर से पैरवी करने की अनुमति भी मांगूंगी।

मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि एसआईआर ने मतदाताओं में भय पैदा कर दिया है और दावा किया कि इस प्रक्रिया से जुड़ी दहशत के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। उनके अनुसार, एसआईआर से संबंधित सुनवाई के लिए कतारों में खड़े लोगों की भी मौतें हुई थीं। सुश्री बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर सत्यापन के नाम पर बुजुर्ग और बीमार नागरिकों को अनुचित रूप से परेशान करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची से मनमाने ढंग से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि मतदाताओं को फॉर्म 7 और 8 जमा करने का अधिकार होने के बावजूद लगभग 54 लाख नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्हाट्सएप आधारित तंत्रों का उपयोग करके नाम हटाने का आरोप लगाया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा बताया। सुश्री बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा दोनों को निशाना बनाते हुए चेतावनी दी कि एसआईआर का इस्तेमाल मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

डीएवी विद्यालयों के राष्ट्रीय खेलों का महाकुंभ

हरिद्वार में 4000 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

पथ प्रवाह, हरिद्वार

डीएवी प्रबंधकर्तृ समिति, नई दिल्ली के प्रधान पद्मश्री डॉ. पूनम सूरी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में डीएवी राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन देश के पाँच प्रमुख स्थलों पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हरिद्वार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में लड़कों के लिए तथा नोएडा में लड़कियों के लिए आयोजित हो रही है, जिसमें देशभर के डीएवी स्कूलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के 18 राज्यों से लगभग 4000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।

डीएवी पब्लिक स्कूलों के निदेशक एवं स्पोर्ट्स संयोजक डॉ. वी. सिंह के कुशल निर्देशन में हरिद्वार में इस खेल प्रतियोगिताओं का विशेष आयोजन किया गया है। वंदना कटारिया स्टेडियम, सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट अकादमी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज (देहरादून) सहित विभिन्न खेल परिसरों में 6 से 8 जनवरी 2026 तक 14 खेल विधाओं–एरोबिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शतरंज, क्रिकेट, टेबल टेनिस, जूडो, कबड्डी, योग, लॉन टेनिस, स्किपिंग रोप, हैंडबॉल, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स–की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं।

इसी क्रम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, हॉकी, रोलर स्केटिंग, आर्चरी, शूटिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग तथा बिलियर्ड्स एवं स्नूकर

जैसी खेल विधाओं का आयोजन भी 6 से 8 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है, जिनमें उत्तराखंड के खिलाड़ी भी पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।

खेल उपलब्धियों की दृष्टि से वर्ष 2025 डीएवी परिवार के लिए ऐतिहासिक रहा है। एक डीएवी विद्यार्थी का विश्व स्केटिंग चैंपियन बनना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में डीएवी के पूर्व विद्यार्थी निषाद कुमार द्वारा हाई-जंप में स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियन रिकॉर्ड बनाना तथा डीएवी हंसराज कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी संदीप चौधरी द्वारा जेवलिन थ्रो स्र44 में रजत पदक जीतना–ये सभी उपलब्धियाँ डीएवी की खेल संस्कृति और समर्पण को दर्शाती हैं।

6 जनवरी 2026 को वंदना कटारिया स्टेडियम, रोशनाबाद (हरिद्वार) में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की फुर्ती, रणनीति, सजगता और अनुकरणीय खेल भावना देखने को मिली। पहले दिन के प्रमुख परिणामों में अंडर-14 फिटनेस एरोबिक्स में दिल्ली ने पहला, हरियाणा ने दूसरा और हिमाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 स्पोर्ट्स एरोबिक्स में झारखंड ने पहला और तीसरा तथा हरियाणा ने दूसरा स्थान हासिल किया। अंडर-19 स्पोर्ट्स एरोबिक्स में हरियाणा पहले, झारखंड दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर रहा।

क्रिकेट और हैंडबॉल मुकाबलों में भी रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जहाँ विभिन्न राज्यों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। अन्य खेलों के परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे।

प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार में इन खेलों के सफल आयोजन में स्थानीय प्रशासन का सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा है, जिसके लिए डीएवी संस्था ने प्रशासन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय एकजुटता का भी सशक्त संदेश दे रहा

एक नजर

दिल्ली में घने कोहरे के कारण 280 से अधिक उड़ानों में देरी

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी और देश के दूसरे हिस्सों में मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 280 से अधिक उड़ानों में देरी की सूचना है और कुछ उड़ानें रद्द हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह चार बजे के बाद दृश्यता घटने लगी और 150 मीटर तक गिर गयी। चार बजे के बाद से ही कैट-3 प्रक्रिया के तहत उपकरण की मदद से परिचालन शुरू कर दिया गया। अमृतसर, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, वाराणसी, रांची, हिंडन (गाजियाबाद) और धर्मशाला में भी दृश्यता कम होने के कारण उड़ानों के परिचालन में देरी हो रही है। दिल्ली हवाई अड्डे की वेवसाइट के अनुसार, आज दिल्ली से जाने वाली कम से कम 20 और दिल्ली आने वाली कम से कम 260 उड़ानों में देरी की सूचना है। कैट-3 की प्रक्रिया के तहत रनवे के साथ-साथ विमान का भी कैट-3 उपकरण से लैस होना जरूरी है। पायलट भी कैट-3 में लैंडिंग और टेकऑफ के लिए प्रशिक्षित होना चाहिये।

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने अपने बड़े भाई के निधन के बाद इमरजेंसी पैरोल की मांग की

नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने अपने बड़े भाई के निधन के बाद इमरजेंसी पैरोल की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। अबू सलेम ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाकर पारिवारिक रस्मों में शामिल होने की अनुमति मांगी है। याचिका के अनुसार, अबू सलेम के बड़े भाई अबू हाकिम अंसारी का 14 नवंबर 2025 को निधन हो गया था। सलेम ने उन्हें पिता समान बताते हुए कहा है कि वह 40वें दिन की रस्में, कुरान ख्वानी, कब्रिस्तान में दुआ और परिवार से मिलने के लिए अस्थायी रूप से जेल से बाहर जाना चाहता है। इस संबंध में अबू सालेम की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें उसे कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाने की अनुमति देने की अपील की गई है।

याचिका में अबू सालेम ने कहा है कि उसके बड़े भाई अबू हकीम अंसारी का निधन हो गया है, जिसके बाद वह परिवार के सदस्यों से मिलना चाहता है। साथ ही, उसने धार्मिक रस्मों में शामिल होने और अपने भाई की कब्र पर जाने की भी अनुमति मांगी है। अबू सलेम का कहना है कि यह उसके लिए भावनात्मक रूप से बेहद कठिन समय है और परिवार के बीच मौजूद रहना उसके लिए जरूरी है।

अबू सलेम ने अदालत को बताया कि जब उसका भाई गंभीर रूप से बीमार था, तब भी उसने पैरोल के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस पर समय रहते सुनवाई नहीं हो सकी। अब भाई के निधन के बाद उसने इमरजेंसी पैरोल के लिए दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया और अदालतों की छुट्टियों के चलते पहले आवेदन पर फैसला नहीं हो पाया।

अबू सलेम नासिक सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। उसकी ओर से दायर याचिका में मानवीय आधार पर राहत देने की मांग की गई है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई कर तय करेगा कि अबू सलेम को इमरजेंसी पैरोल दी जाए या नहीं।

डीएवी के राष्ट्रीय खेलों में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की झलक

पथ प्रवाह, नवीन चौहान

हरिद्वार के विभिन्न खेल मैदानों और आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में इन दिनों डीएवी संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन देश की विविधता और एकता की अनूठी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों से आए डीएवी विद्यालयों के खिलाड़ी यहां अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण उत्साह, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना से सराबोर हो उठा है।

14, 17 एवं 19 आयु वर्ग के अंतर्गत आयोजित इन राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में खिलाड़ी पूरे जोश, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर रहे हैं। हर मुकाबला रोमांच से भरपूर है और दर्शकों को सच्चे खेल कौशल का साक्षी बना रहा है। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और प्रांतों से आए खिलाड़ी एक साथ खेलते हुए 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को जीवंत कर रहे हैं।

आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। डीएवी सेंटेनरी स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज कुमार कपिल के

नेतृत्व में आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन एवं खेल मैदानों की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि खिलाड़ी बिना किसी चिंता के अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इन राष्ट्रीय खेलों में कुल 14 खेल विधाओं–एरोबिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शतरंज, क्रिकेट, टेबल टेनिस, जूडो, कबड्डी, योग, लॉन टेनिस, स्किपिंग रोप, हैंडबॉल, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स–की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों के कौशल, मेहनत और प्रतिस्पर्धी भावना ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। डीएवी प्रबंधकर्तृ समिति, नई दिल्ली के प्रधान पद्मश्री डॉ. पूनम सूरी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आयोजित डीएवी राष्ट्रीय खेल न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच प्रदान कर रहे हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय एकजुटता का भी मजबूत संदेश दे रहे हैं। यह आयोजन सचमुच युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और भविष्य के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को गढ़ने की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम साबित हो रहा है।

आदिवासी राजनीति में बड़ा उलटफेर : बीटीपी के महेश वसावा अब कांग्रेस में, 9 महीने पहले छोड़ी थी भाजपा

दाहोद। करीब 9 महीने पहले भाजपा से इस्तीफा देनेवाले भारतीय ट्रायबल पार्टी (बीटीपी) के स्थापक छोटू वसावा के बेटे महेश वसावा आज कांग्रेस में शामिल हो गए7 महेश वसावा वर्ष 2024 में बीटीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन मात्र एक वर्ष के भीतर ही पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली से असंतोष जताते हुए उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया। अब महेश वसावा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसे आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक संबल माना जा रहा है। महेश वसावा दाहोद में कांग्रेस की 'जन आक्रोश यात्रा' के समापन समारोह में हाथ के साथ हो गए7 दाहोद के कंबोई में आयोजित समापन समारोह में गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने महेश वसावा का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया7 कांग्रेस की यह जन आक्रोश यात्रा भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों, युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठा रही है।

महेश वसावा के कांग्रेस में शामिल होने से डेडियापाड़ा, नर्मदा, दाहोद और भरूच जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इससे पहले महेश वसावा की इन क्षेत्रों में बीटीपी के माध्यम से मजबूत पकड़ रही है और वे वर्ष 2017 में डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके शामिल होने से आदिवासी मतदाताओं में पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा, खासकर 2027 की गुजरात विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए।

यह घटनाक्रम गुजरात की राजनीति में बढ़ती दल-बदल की श्रृंखला का हिस्सा माना जा रहा है और इससे आदिवासी राजनीति में कांग्रेस की ताकत और मजबूत होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महेश वसावा का यह कदम भाजपा के लिए आदिवासी पट्टी में एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com